

राफेल: एक नजर हृधर भी

नारा धान के बाव पल रहे
जबरदस्त तन तनी के बीच प्रांस
निर्मित बहुचर्चित एवं विवादित
युद्धक विमान राफेल गत 10
सितम्बर को औपचारिक रूप से
भारतीय वायुसेना में शामिल कर
लिया गया। इस अवसर पर
अम्बाला छावनी स्थित वायुसेना
स्टेशन पर एक समारोह आयोजित
हुआ जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह, उनकी प्रांसीसी
समकक्ष फ्लोरेंस पार्ले व सेना व
वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी
मौजूद रहे। इससे पहले जब राफेल
ने 29 जुलाई 20 को भारत की
धरती पर अंबाला एयर फ़ेर्स्ट स्टेशन
के रनवे पर अपनी सबसे पहली
लैंडिंग की थी उस समय भी इन
युद्धक विमानों का जोरदार स्वागत
किया गया था। राफेल को 'वॉटर
सेल्यूट' देते हुए दोनों ओर से फायर
ब्रिगेड के स्प्रे के बीच से निकाला
गया था। पूजा पाठ व राफेल को
बुरी नजर से बचाने का सिलसिला

तरह या उस दिन का नाड़ी कपरण
तथा अम्बाला वायुसेना स्टेशन के
आस पास के सुक्ष्म प्रबंध देखने
लायक थे। अम्बाला वायु सेना क्षेत्र
में प्रवेश निषेध होने के बावजूद
मीडिया बता व दिखा रखा था कि
किस समय 5 राफेल की टुकड़ी ने
भारतीय आकाश में प्रवेश किया
और आकाश में ही भारतीय वायु
सेना के दो सुखोई फ़ाइटर विमानों
ने उनकी अगवानी की। अरब
सागर में तैनात भारतीय नव सेना के
युद्ध पोत आई एन एस कोलकाता
द्वारा भी भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश
करने पर राफेल का स्वागत किया
गया। 29 जुलाई को मीडिया के
लगातार प्रसारण ने विशेषकर
अंबाला में कुछ ऐसा माहौल बना
दिया था कि हजारों लोग तेज धूप
के बावजूद अपनी अपनी छतों पर
खड़े होकर वायु सेना के इस नए
मेहमान के दर्शन करने को बेचौन
दिखाई दिए। कुछ स्थानीय
अखबारों ने उस दिन श् अम्बाला में

जाग पालार् गेस रायपुर
लगाकर राफेल के आने की खबर
प्रकाशित की थी। 29 जुलाई के
राफेल की सुरक्षा के दृष्टिकोण
अंबाला जिला प्रशासन द्वारा एवं
फेर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर
परिक्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
लगा दिया गया था। प्रशासन हाई
एलटर पर था तथा राफेल लैंडिंग वे
दौरान छतों से फेटोप्रापी करना वे
लोगों का जमावड़ा लगाना पूरी तरह
से प्रतिबंधित था। पक्षी उड़ाने वे
पतंगबाजी करने तक पर रोक थीं
जाहिर है यह सभी एहतियाती उपाय
इसीलिये किये जा रहे थे ताकि
बेशकीमती राफेल की सुरक्षा न
कोई चूक या कमी न रह जाने पाए
राफेल के भारतीय वायुसेना और
शामिल होने से पूर्व भी अंबाला
वायु सेना स्टेशन मिग-21 वे
जगुआर जैसे युद्धक विमानों का
केंद्र रहा है। देश के पश्चिम क्षेत्र का
महत्वपूर्ण निगरानी केंद्र होने वे
कारण यहाँ दशकों से मिग-21 वे

जुझार त्रिवेषः जन्मा निवानतो उड्डन
भरते रहते हैं। कम से कम ऊँचाई
पर भी उड़ने की क्षमता खबरें वाले
इन विमानों की सुरक्षित उड्डन के
मद्देनजर ही इस हवाई क्षेत्र के
आसपास के इलाके में तीन मंजिला
इमारत बनाए जाने पर कानूनन रोक
है। परन्तु इसी शहर में मोबाइल
टावर्स को भरमार ज़रूर है। राफेल
की भारी कीमत और चीन से चल
रहे वर्तमान तनावपूर्ण हालात को
देखते हुए न केवल समस्त
भारतवासियों बल्कि सभी सरकारी
व गैर सरकारी विभाग के लोगों की
भी जिम्मेदारी है कि वे राफेल की
सुरक्षा सुनिश्चित करें और इस दिशा
में अपना हार संभव योगदान भी दें।
पिछले दिनों मैंने रात के समय
अम्बाला के आस पास विशेषकर
शहरी क्षेत्र का भ्रमण इसी मकसद
से किया ताकि देख सकूँ कि राफेल
की आमद पर जश्न मनाने वाला
देश अखिल राफेल की सुरक्षा के
प्रति कितना गंभीर है। मैंने पाया कि

350 रुपू ले लेकर 200 रुपू तक का ऊंचाई वाले अधिकांश मोबाइल टावर्स के शीर्ष का संकेत देने वाली लाल लाईट बुझी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि वो एस एन एल व रेलवे जैसे माइक्रोबेव टावर्स जो के लगभग 350 से लेकर 500 मुट्ठ तक की ऊंचाई रखते हैं उनमें भी कई टावर्स के शीर्ष पर आवश्यक रूप से जलने वाली संकेत रूपी लाल बत्ती बुझी हुई थी। ऐसे में योग्य हो या जुग्य आर या अब भारतीय वायु सेना में नया शामिल हुआ रफेल, जरुरत पड़ने पर या अपनी नियमित उड़ान के समय भी कभी कभी बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। रफेल की सुरक्षा के प्रति वायुसेना के अधिकारियों की भी चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गत 10 सितंबर को रफेल के औपचारिक रूप से वायुसेना के बड़े में विधिवत शामिल होने से पूर्व ही भारतीय वायु सेना के निरीक्षण और सुरक्षा नीहानदराक, एक नारायण नानवद्र सिंह ने, हरियाणा की मुख्य सचिव, केशनी आनंद अरोड़ा को एक अधिकारिक पत्र लिखकर अंबाला एयर फोर्स स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में कच्चा निपटाने के लिए त्वरित उपाय करने का अनुरोध किया है। ऐसा पत्र कच्चे के चलते पक्षी इकट्ठा होने व इनके उड़ने के कारण रफेल लड़ाकू विमान की सुरक्षा को होने वाले संभावित खतरे के दृष्टिकोण से लिखा गया है। गैरतलब है कि अंबाला वायुसेना क्षेत्र में पक्षियों की संख्या अधिक होने कारण टकराव होने से इन बेशकीमती विमानों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। वायु सेना ने स्थानीय शहरी निकाय विभाग से भी मांग की है कि कम से कम अम्बाला एयरफील्ड के आसपास 10 किलोमीटर की परिधि में पतंगों व बड़े पक्षियों की गति विधि को कम करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को तत्काल कार्यान्वित किया जाए। वायु क्षेत्र से उपरुपुल धूरा ने उन्नुक लाइट पर्स मैनेजमेंट संबंधी प्लांट तत्काल स्थापित किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि वायुसेना द्वारा अंबाला वायु सेना स्टेशन के आसपास कबूतर प्रजनन गतिविधि को निषिद्ध व नियंत्रित करने के लिए भी प्रशासन से कहा गया है। जाहिर है कि रफेल के शुभागमन मात्र से ही रफेल की जरूरत नहीं पूरी होने वाली बल्कि इसके रखरखाव की सबसे अहम जरूरत अर्थात् इसकी पूर्ण सुरक्षा तथा इसके लिए निर्बाध हवाई रास्ता उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारों को आपसी तात्त्व मेल से यथाशीघ्र इसकी सुरक्षा संबंधी सभी उपाय करने चाहिए। सभी ऊँचे टावर्स की लाल बत्ती रात के समय तत्काल जलनी चाहिए और हवाई क्षेत्र के आसपास से कूड़े के निपटान का काम व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की स्थापना आदि जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।

ਲਖਪਾਦਖਗਚ

ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਰਖਤਾਰ

गाला दुनिया का थौंथा देश बन गया है। महत्वपूर्ण बात यह भी कि बीते साल की विफलता को पीछे छोड़ भारत ने देश में विकसित तकनीक से यह कामयाबी हासिल की है। इस तकनीक के जरिये धनि से छह गुना अधिक गति वाली वर्जन मिसाइलों से लक्ष्य को मेटा जा सकता है। निस्सदैह भारत की सीमाओं के आसपास जिस तरह की परिस्थितियाँ विकसित हो रही हैं, उसका मुकाबला उन्नत रक्षा तकनीकों के जरिये संभव है, जिसमें अगली पीढ़ी की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों में इस तकनीक को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी ओर आलमिर्ण भारत अग्रियान की दिशा में भी यह एक कामयाबी है जिसके लिये इसे विशुद्ध स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। आगे वाले दिनों में इस तकनीक के उन्नत स्वरूप के जरिये कम लागत वाले उपग्रहों के प्रयोगण में मटद मिल सकेंगी। दरअसल, चीन की दबंगई और पाक के मासूबों के बीच भारत वर्जन एवं बैलिस्टिक मिसाइलों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित कर रहा है, जिसमें रूस से हासिल ब्रह्मोस, पृथ्वी, अरिंग और टैक्टोरी मिसाइलों भी शामिल हैं। यह रहे कि बीते साल मार्घ में भारत ने अंतरिक्ष में लक्ष्य नेटकर अंतरिक्ष-रोधी मिसाइल का परीक्षण करके दुनिया को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया था। निस्सदैह भारत शक्ति संतुलन के लिये अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों को विकसित कर रहा है। लेकिन संदेश यह भी है कि यदि देश के सामने विकट परिस्थितियाँ पैदा हुईं तो देश उसका मुकाबला भी कर सकता है। आज भारत धनि की रपतार से छह गुनी तीव्रता से मिसाइल व यान प्रयोगण की शक्ति प्राप्त कर चुका है। डीआरीओ द्वारा तैयार किये गये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफ्ट परीक्षण के बाद उम्मीद जगी है कि भारत शीघ्र ही एक शक्तिशाली लॉकेमेंट इंजन के जरिये हाइपरसोनिक शक्ति हासिल कर लेगा जो विमानान और अंतरिक्ष अभियानों में तेज रपतार हासिल करने में मददगार साबित होगा। हालांकि, पिछली यह तकनीक मानव रहित तीव्र गति वाले विमानों में उपयोग करने वाली होगी, मगर आशा है कि मविष्य में भारत इनसान वाले हाइपरसोनिक यान तैयार कर सकेंगा। निस्सदैह यह स्वदेशी तकनीक कम खर्ची है और निकट भविष्य में कम लागत में उपग्रहों के प्रयोगणों में मददगार साबित होगी। दरअसल, यह तकनीक वायुसंकल क्षेत्र में अलग तरह से काम करती है, जिसका इस्तेमाल मिसाइल प्रयोगण में किया जाता है। वहीं अंतरिक्ष अभियानों के लिये उन्नत तकनीक की ज़रूरत होती है, जिसमें रूस एवं चीन ने कामयाबी हासिल की है। बहरहाल, भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी देश के रक्षा तंत्र को मजबूती देगी। हाइपरसोनिक स्पीड के जरिये मिसाइलें दूरमान के लक्ष्य को ज्यादा तेजी से भेज पाती हैं जिसकी गति से छह गुना अधिक रपतार से लक्ष्य पर वार करती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि उन्नत रक्षा तकनीकों के दौर में युद्ध परंपरागत तकनीक के बूते नहीं लड़ा जा सकता।

प्रधान के सकत गम्ल ह। बृहस्पतिवार को दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई तीन घटे की बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति बनती नजर आई। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर व उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच हुई मुलाकात में स्पष्ट किया गया कि भारत एलएसी पर जारी तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता और चीन को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि पड़ोसी देश होने के नाते कुछ मुद्दों पर मतभेद स्वाभाविक हैं लेकिन इसे असहमतियों के उचित संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर चीन की कथनी-करनी के पुराने अनुभवों से सबक लेकर भारत ने सुरक्षा व सामरिक रणनीतियों को नये सिरे से निर्धारित करना शुरू कर दिया है। बृद्धवार को हिंद महासागर में चीन की धेराबंदी करने के नजरिये से भारत व जापान के बीच हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मास्को में संपन्न एससीओ की बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बयान के हवाले से कहा है कि भारत व चीन के रिश्ते मौजूदा वक्त में दोरा हो पर खड़े हैं, जिन्हें सही दिशा में बढ़ाने की जरूरत है। यह भी गया है कि दाना दशा के बिद्युत मंत्रियों में एलएसी विवाद को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। तब हुआ कि दोनों ही पक्ष इन नेताओं व बीच हुई सहमतियों से सलाह लें और असहमतियों को तनाव में नहीं बदलने देंगे। मौजूदा स्थिति को दोनों पक्षों के हित में न मानते हुए सेनेट बातचीत को जारी रखने की बाहर हुई। सीमा पर उचित दूरी बनाने व तनाव कम करने के प्रयासों पर भी सहमति हुई।

साथ ही तनाव टालने के लिये मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉलों का पालन करने की बाबत कही गई। कुल मिलाकर दोनों देशों ने इस बात को स्वीकारते हैं कि सीमा पर तनाव कम होना चाहिए, रासायनिक व बरकरार रहनी चाहिए तथा भरोसे बढ़ाने के लिये कदम उठाने का जरूरत है। ऊँझेखनीय है कि इसपर पहले एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष वैई फेंग राम मुलाकात की थी और आगे विदेश मंत्रियों की बातचीत के लिये पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। वहीं बृहस्पतिवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत के अलावा एलएसी पर सेन्य बातचीत भी हुई। इससे पहले भी कोर कमांडर स्तर के कई दौर की बातचीत हो चुकी है। दरअसल

A close-up photograph showing a medical syringe filled with a bright blue liquid, likely a vaccine. The syringe has 'SINGLE USE ONLY' and '(S)AM' printed on it. A gloved hand in a blue medical glove holds both the syringe and a white vial with a green cap. The vial has a black label with the text '11-05-2018', 'S002045', and '11-05-2021'. The background is a plain, light-colored wall.

एक तरफ देश की रेलवे के निजीकरण की कावायद चल रही है दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की रेल पटरियों के किनारे बसी अवैध अदालत से सङ्क तक संघर्ष करने की बात कर रहा है। इस सियासत में रेल प्रशासन भी उलझा हुआ है। रेलवे का कहना है कि संपीड़न कोर्ट हटाने पर रोक नहीं लगाएगी और न ही इसमें किसी भी तरह का राजनैतिक व अन्य हस्तक्षेप होगा। इसी के साथ रेलवे ट्रैक के आगमन मामला है। झुगियों में रहने वाले पटरी पर शौच करते हैं। गंदगी की बजह से पटरियों व सिंगल के अधिकाधिक रेलवे स्टेशनों के नजदीक अवैध झुगियां बनी हुई हैं। इन झुगियों में अपराधिक प्रवृत्ति के लिए भी अपना अड़ा बना लेते हैं। जरूर कार्रवाई होती रही। अभियान के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की। पटरियों के किनारे वर्तमान हालात रेलवे अधिकारियों की लाप्पवाही का

वस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि केवल दिल्ली नहीं अपितु पूरे भारत में रेल पटरियों के किनारे रेलवे की जमीन पर अवैध झुगियों एवं अवैध निर्माणों की भरमार है। एक अनुमान के मुताबिक अगर दिल्ली में पचास हजार के लगभग तो अन्य राज्यों में भी इसी औसत से अवैध बस्तियों का निर्माण हो चुका है और चल रहा है। यही नहीं इन पटरियों के किनारे झुगियों ही नहीं बल्कि आलीशान भवन भी आपकों नजर आ जाएंगे। गलती रेलवे ही नहीं करता बल्कि इस अवैध कब्जों को बिजली कनेक्शन और आधार, राशनकार्ड उपलब्ध हो जाता है तो लगता है कि सभी अवैध कब्जे को ऑर्ख मूदकर वैध बना रहे हैं। लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद रेलवे ट्रैक किनारे बसी झुगियां हटाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। सभी दलों के नेता एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विषक्षण लगातार प्रदेश सरकार से झुगी वासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहा है। इसके अलावा विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। उधर, आप का कहना है कि किसी

कचरा हटाने का भी आदेश दिया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में रेलवे पटरी के किनारे अतिक्रमण गंभीर समस्या है। अतिक्रमण कर बनी द्विग्यायों से न सिफेरेलवे की विकास योजनाएं बाधित हो रही है, बल्कि सुरक्षित रेल परिचालन में भी यह बड़ी समस्या है। इसके साथ ही यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण समस्या दूर नहीं हो पा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अतिक्रमण हटाने की उम्मीद बढ़ी है। अभी केवल दिल्ली की बाँत करे तो राजधानी दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में रेलवे ट्रैक के किनारे द्विग्यायों की संख्या बढ़ती जा रही है। दया बस्ती, आजादपुर, ओखला, तिलक ब्रिज, वजीरगढ़, शकूरबस्ती, किशनगांज, सराय रोडिल्ला में स्थिति ज्यादा खराब है। रेलवे अधिकारी बताते हैं कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंफ्रारेट बोर्ड (डीएयूसआइबी) के अनुसार रेलवे की 60 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अवैध तरीके से लगभग 48 हजार द्विग्यायां बनी हुई हैं, जिनमें से दस हजार से ज्यादा सेफ्टी जोन में (ट्रैक से 15 मीटर के अंदर) हैं। अतिक्रमण सीधे रेल

होती है। कई बार गंदगी की वजह से मरम्मत कार्य भी ठीक से नहीं हो पाता है। लगातार मल-मूत्र त्वायग किए जाने की वजह पटरी व उसके आसपास की मिट्टी का क्षण होता है। यह सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरनाक है। अतिक्रमण की वजह से निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। रेलवे कर्मचारी व अधिकारियों के लिए कॉलोनी, रेलवे बिछाने का काम भी प्रभावित हो रहा है। दया बस्ती व शकूर बस्ती में ग्रेड सेपरेटर का काम भी वर्षों से पूरा नहीं हो सका है। नई दिल्ली से तिलकबिज के बीच अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने में भी अतिक्रमण की वजह से काफी वक्त लगा। दिल्ली में सड़कों पर बाहनों की भीड़ कम करने के लिए रिंग रेल का विकास कीया जाना है। वर्ष 2016 में ही दिल्ली सरकार के आग्रह पर रेल मंत्रालय ने इसकी संभावना पर काम शुरू किया था, लेकिन पटरी किनारे अतिक्रमण इसमें सबसे बड़ी बाधा है। रिंग रेल पर ट्रेन की संख्या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पटरी बिछानी होगी। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाए बगैर यह काम नहीं हो सकता है।

दूसरी ओर सेफ्टी जोन में भी अतिक्रमण होने की वजह से स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेनों को गति धीमी गरनी पड़ती है। वहीं, कई बार सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ट्रेन आउटर पर खड़ी हो जाती है। इसका पर्याय उठाकर अपराधी ट्रेन में सवार होकर लूटपाट, छेड़खानी जैसे करते हैं। दिल्ली में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके साथ ही झुग्गियों में रहने वाले अक्सर ट्रेन पर पथराव भी करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस व वर्दे भारत एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों पर झुग्गियों से पथराव हो चुका है। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने में सबसे बड़ी बाधा सियासत है। अवैध झुग्गियों में रहने वालों के पास आधार कार्ड से लेकर मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं। इनके बोट के लालच में प्रत्येक पार्टी अतिक्रमण विरोधी कार्बाई शुरू होते ही विरोध में खड़ा हो जाता है। चार वर्ष पहले शकूरबस्ती में अतिक्रमण हटाने को लेकर भी खूब सियासत हुई थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कब्जे की शुरूआत से लेकर बस्तियां बन जाने तक रेलवे और आरपीएफ के अधिकारी अंख मूंदकर और मौन रहे।

उदाहरण हैं अगर समय रहते अफसर इस ओर कार्बाई करते तो आज यहाँ झुग्गियां न होतीं। यह भी सच है कि झुग्गियों में रहने वालों लोगों को सुविधाएं कुछ कथित ठेकेदार उपलब्ध कराते हैं। यह ठेकेदार उनके द्वारा बीना गया पूरा कूड़ा खरीदते हैं। ठेकेदार की शह पर ही अन्य राज्य से आए लोग रेल पटरी के किनारे बस गए हैं। पटरी किनारे झुग्गियों में रहने के लिए ठेकेदारों को इसका किराया भी देते हैं। अब मध्यम प्रदेश की बॉत करे तो धमतरी द्य धमतरी रेलवे स्टेशन का दायरा अवैध कब्जे के कारण सिमटा जा रहा है। इस समस्या पर सख्ती दिखाते हुए अब रेलवे ने अपनी जमीन पर अनधिकृत रुप से काबिज लोगों को नोटिस जारी कर 4 दिनों के भीतर अवैध कब्जा हटाने कहा जा रहा है। मुझ्हें की बॉत करे या फिर कानपुर, लखनऊ की बॉत करे या जबलपुर, पटना की बॉत करे या अजमेर, भोपाल, हिन्दुस्तान का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं जहाँ रेलवे की जमीन पर अवैध बस्तियों का निर्माण न हो। ऐसे में बोट बैंक राजनीति, जिम्मेदारों की अनदेखी, ठेकेदारों के गठजोड़ से रेलवे की पटरियाँ अवैध कब्जे से हो जाएंगी।

